RNI Title-Code :- RAJBIL27027
www.nagaurdaily.com
Email. nagaurdaily0@gmail.com

नागौर डेली न्यूज़

नागौर, कुचामनसिटी, डीडवाना, मकराना, परबतसर, जायल
मेड़तासिटी, खींवसर, डेगाना व नावां से एक साथ प्रकाशित

अहसास बदलाव का...

42 दिन चलेगा क्रिकेट का महासंग्राम

टैस्ट क्रिकेट की सबसे पुरानी जंग एशेज सीरीज बुधवार से शुरू होगी। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होने वाली यह सीरीज 42 दिन चलेगी। इसमें 5 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया अपने नए कप्तान पैट कमिंस के साथ उतरेगी। हम आपको इस मेगा टूर्नामेंट के बारे में वह सब कुछ बता रहे हैं, जिन्हें जानने के बाद एशेज को लेकर आपके रोमांच में और भी इजाफा होगा।

सीएम का आरोप- गजेंद्र शेखावत ने हड़पा निवेशकों का पैसा

शाह के दफ्तर में रची गई थी सरकार गिराने की साजिश : सीएम गहलोत

जयपुर.

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर बड़ा हमला बोला है। गहलोत ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में कहा- नॉर्थ ब्लॉक में अमित शाह के ऑफिस में बैठकर राजस्थान सरकार गिराने का षड्यंत्र रचा गया था। अमित शाह फेल हो गए। षड्यंत्र में शामिल एक मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत तो राजस्थान के ही थे। उनकी आवाज तो टेप में आई थी। गजेंद्र सिंह शेखावत अगर आवाज का नमूना दें तो पोल खुल जाएगी। गहलोत ने शेखावत पर निवेशकों का पैसा हड़पने वाली क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी के साथ संबंध होने का आरोप लगाया।

जनता से लूटे पैसे वापस करने की क्या तरकीब है? गहलोत ने कहा- किस रूप में ये नेता और केंद्रीय मंत्री बन गए। पश्चिमी राजस्थान के लोग बाड़मेर-जैसलमेर तक रो रहे हैं। आदर्श सोसाइटी, नवजीवन सोसाइटी की तरह तीसरी संजीवनी सोसाइटी के चार लोग जेल में बैठे हैं। अगर इनमें ईमानदारी है तो बताएं कि जनता से लूटे हुए पैसे वापस देने की क्या तरकीब है। ऐसे लोग केंद्र में मंत्री बनकर बैठे हैं।

अमित शाह के विधायक तक सहयोग को तैयार नहीं-अमित शाह के 2023 तक सरकार नहीं गिराने के सवाल पर गहलोत ने कहा- उनके हाथ में है क्या सरकार गिराना। उन्होंने प्रयास करके देख लिया। वे फेल हो गए। इनकी कितनी दुर्ग?ति हुई, इनके खुद के एमएलए सहयोग करने को तैयार नहीं हुए। उस समय राजस्थान से बीजेपी विधायकों को पोरबंदर ले जाने के लिए दो-दो प्लेन भेजे गए थे। एक प्लेन मुश्किल से गया, दूसरा खाली गया। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी? बीजेपी के एमएलए पर शक करने लग गए कि कांग्रेस के टूटे न टूटे हमारे खुद के विधायक नहीं टूट जाएं। जनता ने साथ दिया तो राजस्थान में माहौल ऐसा बन गया कि कोई इनका साथ देने को तैयार नहीं था। चाहे इनकी पार्टी के एमएलए ही क्यों न हो। यह हमारी बहुत बड़ी जीत थी।

सरकार गिराने में शामिल लोगों की पोल खुल गई- गहलोत ने कहा- सरकार गिराने का षड्यंत्र धर्मेंद्र प्रधान के घर में रचा गया था। उनके साथी संगी थे, जिन्होंने सारी व्यवस्थाएं की थीं। उनकी पोल खुल गई है। सरकार का बचना राजस्थानवासियों के लिए तो राहत की बात है। पूरे देश में चर्चा होती है कि राजस्थान की क्राइसिस को फेल किया। राजस्थान ने जो इतिहास बनाया है, वह लोकतंत्र को बचाने के काम आएगा। ये लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे। राजस्थान की जनता और विधायकों ने एनडीए सरकार का षड्यंत्र फेल कर दिया। षड्यंत्र में शामिल एक मंत्री तो राजस्थान के ही थे। उन्होंने ओएसडी लोकेश शर्मा पर दिल्ली में मुकदमा कर दिया।

किसान आंदोलन खत्म करने का फैसला टला

संयुक्त किसान मोर्चा आज लेंगे अंतिम निर्णय

चंडीगढ़।

दिल्ली बॉर्डर पर चल रहा किसान आंदोलन आज खत्म हो सकता है। सिंघु बॉर्डर पर मंगलवार को हुई संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक भी इसी मुद्दे पर हुई थी। अब केस वापसी को लेकर एक पेंच फंस गया है। सरकार का कहना है कि आंदोलन खत्म करने के बाद केस वापसी का ऐलान करेंगे। दूसरी ओर, किसान चाहते हैं कि सरकार अभी इस पर ठोस आश्वासन दे। किसान नेता हरिंदर सिंह लक्खोवाल ने कहा कि किसान आंदोलन पर आज ही घोषणा की तैयारी थी, लेकिन सरकार ने बीच में पेंच फंसा दिया। अगर सरकार संशोधित प्रस्ताव भेजेगी तो आंदोलन पर फैसला हो जाएगा।

कैसे निकलेगा इसका रास्ता : केस वापसी और मुआवजे के मुद्दे पर केंद्र से बातचीत के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने 5 मेंबर्स की कमेटी बनाई है। जिसमें पंजाब से बलबीर राजेवाल, उत्तर प्रदेश से युद्धवीर सिंह, मध्यप्रदेश से शिव कुमार कक्का, महाराष्ट्र से अशोक धावले और हरियाणा से गुरनाम चढ़ूनी शामिल हैं। इनकी गृह मंत्रालय के साथ अंतिम मीटिंग हो सकती है।

मुआवजा : किसान लीडर्स ने कहा कि इस पर सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी दी है, लेकिन हमारी मांग है कि केंद्र सरकार पंजाब मॉडल की तरह मुआवजे की मांग को माने, जिसमें 5 लाख का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी का जिक्र है। इससे पीड़ित परिवारों को न्याय मिलेगा। किसान नेता बलबीर राजेवाल ने कहा कि सरकार ने एमएसपी के मामले में कमेटी की बात की है। जिसमें दूसरे संस्थानों, राज्य और अफसरों के साथ किसानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। हमें इस पर ऐतराज है। ऐसे लोग कमेटी में नहीं होने चाहिए, जो सरकार के साथ कानून बनाने में शामिल रहे। अशोक धावले ने कहा कि एमएसपी कमेटी में किसान संगठनों और संयुक्त किसान मोर्चा का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। एक साल से हमने आंदोलन लड़ा।

12 सांसदों के निलंबन पर विवाद, सरकार ने माफी मांगने को कहा, विपक्ष का इंकार

नई दिल्ली।

संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन 12 सदस्यों को पूरे सत्र के लिए निलंबित करने पर राज्यसभा में जारी गतिरोध दूसरे सप्ताह मंगलवार को भी बना रहा और सत्ता पक्ष एवं विपक्ष अपने रुख से पीछे हटने को तैयार नहीं दिखे। सरकार ने मंगलवार को उच्च सदन में कहा कि यदि निलंबित सदस्यों ने माफी नहीं मांगी तो उसे शोरगुल में विधेयक पारित कराने को मजबूर होना पड़ेगा वहीं विपक्ष ने माफी मांगने से साफ इंकार करते हुए कहा कि इन 12 सदस्यों का निलंबन सरकार को वापस लेना चाहिए।

दो बार के स्थगन के बाद उच्च सदन की बैठक जब अपराह्न तीन बजे शुरू हुई तो संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा, ''हम सरकार की तरफ से कहना चाहते हैं कि हम शोरगुल में विधेयक पारित नहीं करना चाहते। मैं आपके (आसन) माध्यम से अनुरोध करता हूं कि वे (निलंबित विपक्षी सदस्य) माफी मांगें।''

गोरखपुर में पीएम ने किया विरोधियों पर वार

लाल टोपी वालों को सिर्फ लाल बत्ती से मतलब, ये यूपी के लिए खतरे की घंटी : पीएम मोदी

गोरखपुर।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को गोरखपुर पहुंचे। मौका तो था 10 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन का, लेकिन प्रधानमंत्री ने मंच का इस्तेमाल विरोधियों पर तंज कसने के लिए किया। समाजवादी पार्टी का नाम लिए बगैर मोदी ने कहा, आज पूरा यूपी भलीभांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। इन्हें आपके दुख-तकलीफों से कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री बोले, लाल टोपी वालों को घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए सत्ता चाहिए। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है, आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट हैं, यानी खतरे की घंटी। सब जानते थे कि गोरखपुर में एम्स की मांग बरसों से हो रही थी, लेकिन 2017 से पहले जो सरकार चला रहे थे, उन्होंने एम्स के लिए जमीन देने में हर तरह के बहाने बनाए। सब जानते थे कि गोरखपुर का फर्टिलाइजर प्लांट, इस पूरे क्षेत्र के किसानों के लिए, यहां रोजगार के लिए कितना जरूरी था, लेकिन पहले की सरकारों ने इसे शुरू करवाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई।

10 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया

मोदी ने मंगलवार को गोरखपुर में 10 हजार करोड़ से बने खाद कारखाना, एम्स और बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज के रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। पीएम ने कहा कि पहले की सरकारों ने अपराधियों को संरक्षण देकर कका नाम बदनाम कर दिया था। आज माफिया जेल में हैं और निवेशक दिल खोल कर यूपी में निवेश कर रहे हैं। यही डबल इंजन का डबल विकास है।

आजादी के बाद से इस सदी की शुरुआत तक देश में सिर्फ 1 एम्स था। अटल जी ने 6 और एम्स स्वीकृत किए थे। बीते 7 वर्षों में 16 नए एम्स बनाने पर देशभर में काम चल रहा है। हमारा लक्ष्य ये है कि देश के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज जरूर हो। गोरखपुर और बस्ती डिवीजन के 7 जिलों में दिमागी बुखार के मामले करीब 90% तक कम हो गए हैं। जब मैंने एम्स का शिलान्यास किया था, तो मैंने कहा था कि हम दिमागी बुखार से इस क्षेत्र को राहत दिलाने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। हमने दिमागी बुखार फैलाने की वजह को दूर करने पर भी काम किया और इसका उपचार भी किया। गोरखपुर में एम्स और आईसीएमआर रिसर्च सेंटर बनने से अब इंसेफेलाइटिस से मुक्ति के अभियान को और मजबूती मिलेगी।

चांद पर जा सकता है पहला भारतीय

वॉशिंगटन.

अमेरिकी स्पेस एजेंसी नाशा ने अपने मून मिशन के लिए 10 ट्रेनी एस्ट्रोनॉट को चुना है। इनमें भारतीय मूल के अनिल मेनन भी शामिल हैं। 45 साल के अनिल नाशा की क्लास 2021 का हिस्सा बनेंगे। अनिल अमेरिकी एयरफोर्स में लेफ्टिनेंट कर्नल हैं और स्पेसएक्स में फ्लाइट सर्जन भी रहे। इस क्लास के लिए चुने गए 10 लोगों में 6 पुरुष और 4 महिलाएं हैं। नाशा 50 साल बाद चांद पर इंसान भेजने के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। अनिल मेनन भारत में भी करीब एक साल गुजार चुके हैं। तब वे यहां पोलियो अभियान की स्टडी और उसके सपोर्ट के लिए भेजे गए थे। चंद्रमा पर अब तक भारत का कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं गया है। हालांकि अब तक भारत के 4 लोग अंतरिक्ष में जा चुके हैं। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश

शर्मा थे। उनके अलावा भारतीय मूल की कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स और राजा चारी अंतरिक्ष में गए हैं। अगर अनिल नाशा के मून मिशन का हिस्सा बनते हैं तो वे चंद्रमा पर जाने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति होंगे।

नाशा ने मून मिशन के लिए सिलेक्ट किए 10 ट्रेनी एस्ट्रोनॉट, इनमें भारतीय मूल के अनिल मेनन भी

2 साल की ट्रेनिंग से गुजरेंगे अनिल

मून मिशन के लिए 12 हजार लोगों के आवेदन आए थे, इनमें ट्रेनिंग के लिए सिर्फ 10 को चुना गया है। ये लोग अगले साल जनवरी में टेक्सास के जॉनसन स्पेस सेंटर पर रिपोर्ट करेंगे। इसके बाद उन्हें 2 साल की ट्रेनिंग से गुजरना होगा। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ये सभी नासा की आर्टेमिस जेनरेशन प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। इस प्रोग्राम के तहत नासा 2025 में पहली महिला और एक पुरुष को चांद की सतह पर भेजने की योजना बना रहा है।

कौन हैं अनिल मेनन?

अनिल मेनन के माता-पिता भारतीय और यूक्रेनियन थे। वे अमेरिका के मिनेसोटा में पले-बढ़े हैं। उन्होंने 1999 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से न्यूरोबायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया। 2004 में कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। स्टैनफोर्ड मेडिकल स्कूल से उन्हें डॉक्टर की डिग्री भी मिली हुई है। उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर नाशा के कई अभियानों के लिए क्रू फ्लाइट सर्जन का भी रोल निभाया है।

21वीं सदी की दूसरी तिमाही में भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था में दबदबा रहेगा

लारेंस के कथन पर और विचार करने के पहले हमें बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के इस बयान पर भी गौर करना होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि 'कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील (संप्रग) गठबंधन अब नहीं है।' ममता ने यह वक्तव्य मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अध्यक्ष शरद पवार से भेंट के पश्चात दिया। विपक्षी दलों के हालिया आचरण से स्पष्ट है कि उनकी लड़ाई भाजपा के साथ बाद में और कांग्रेस के खिलाफ पहले है। ये दल उस स्थान को प्राप्त करने के लिए संघर्षरत हैं, जो एक मुख्य विपक्षी दल के रूप में अभी कांग्रेस के पास है।

पिछले दिनों प्रख्यात अर्थशास्त्री, अमेरिका की राष्ट्रीय आर्थिक परिषद के पूर्व निदेशक और पूर्व राज्यकोष सचिव लारेंस हेनरी समर्स ने कहा कि '21वीं सदी की दूसरी तिमाही में भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था में दबदबा होगा। भारत अगले 15 वर्षों तक दस प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त कर सकता है, लेकिन इसके लिए यहां एक ऐसी सरकार की आवश्यकता होगी, जो न केवल अर्थव्यवस्था को सक्रिय रखे और उसमें सुधार लाए, बल्कि आर्थिकी को सरकारी सख्ती और नियंत्रण से मुक्त रखने के लिए तैयार भी रहे। इसके लिए राजनीतिक स्थिरता की भावना होना आवश्यक है।' लारेंस के विश्लेषण को इसलिए भी गंभीरता से लेने की आवश्यकता है, क्योंकि हालिया इतिहास में अमेरिकी आर्थिकी को आकार देने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

अर्थशास्त्री लारेंस हेनरी समर्स ने भारत के उज्ज्वल भविष्य में राजनीतिक अस्थिरता और ऐतिहासिक कठिनाइयों को अवरोधक बताया है। क्या भारत में 1989-2014 का कालखंड समर्स के इन्हीं विचारों को प्रमाणित नहीं करता? तत्कालीन राजनीतिक अस्थिरता और उसकी सतत संभावना ने भारत से बड़ी भारी कीमत वसूली है। दो वर्ष पहले आई फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अनुसार 1985 में 'लोकतांत्रिक' भारत और 'अधिनायकवादी' चीन में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद बराबर 293 डालर प्रति व्यक्ति था, किंतु 2017-18 में चीन की प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में चान गुना अधिक हो गई। आज चीन एक बड़ी विश्व शक्ति है, जो भारत, अमेरिका सहित शेष विश्व के कई देशों के लिए चुनौती बना हुआ है। इन 25 वर्षों में जहां चीन में मजबूत और सक्षम नेतृत्व रहा, वहीं भारत की केंद्रीय राजनीति में इसका नितांत आभाव दिखा। इस बिंदु की सच्चाई चीन स्थित थ्री गार्जेज बांध और भारत स्थित सरदार सरोवर बांध से स्पष्ट है। जिस 6,300 किमी लंबी और एशिया की तीसरी बड़ी यांगत्जी नदी पर चीनी बांध बना है, वह 13 नगरों, 140 कस्बों और 1,350 गांवों को लील चुका है। इस बांध से 13 लाख लोग विस्थापित हो गए। चीन ने इस बांध को

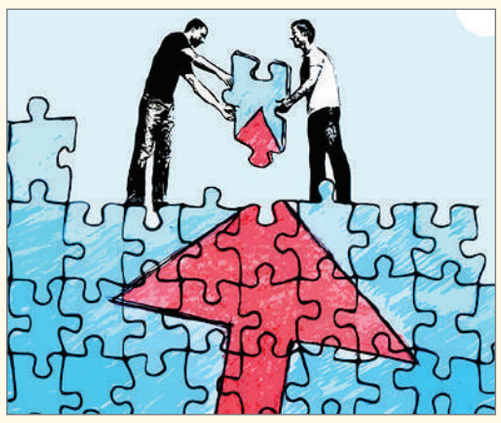

दस वर्षों (1994-2003) में बना दिया। इसके विपरीत भारत में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध को पूरा करने में 56 वर्ष लग गए, जिसने 178 गांवों को प्रभावित किया और जिससे चीनी बांध की तुलना में बहुत कम लोग विस्थापित हुए। इसकी नींव 1961 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी, जिसके वित्तपोषण के लिए विश्व बैंक वर्ष 1985 में सहमत हुआ। जैसे ही अप्रैल 1987 में नर्मदा बांध का निर्माण प्रारंभ हुआ, नर्मदा बचाओ आंदोलन ने मानवाधिकार-पर्यावरण संरक्षण के नाम पर इसका विरोध करना शुरू कर दिया। 1995 में सर्वोच्च न्यायालय का रुख करके इस पर रोक लगवा दी, जो चार वर्षों तक जारी रही। फिर अगले 18 वर्षों में अदालती चक्करों में फंसे रहने और अन्य अवरोधकों को पार करके यह बांध 2017 में पूरी क्षमता के साथ शुरू हुआ, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया। नर्मदा बांध को पूरा करने में भारत को चीन की तुलना में पांच गुना अधिक समय लगा। इसका सबसे बड़ा कारण 1989-2014 के बीच भारत की वे समझौतावादी खिचड़ी गठबंधन सरकारें रहीं, जिसमें कुछ अपवादों को छोड़कर राष्ट्रहित गौण रहा तो जोड़तोड़ की राजनीति हावी रही। इस 25 वर्ष के कालखंड में भारत में दस सरकारें और आठ प्रधानमंत्री हुए-वीपी सिंह 11 माह, चंद्रशेखर चार माह, नरसिंह राव पांच वर्ष, अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन, एचडी देवेगौड़ा 11 माह, इंद्रकुमार गुजराल 11 माह, वाजपेयी फिर से 13 माह एवं पांच वर्ष और डा. मनमोहन सिंह 10 साल। इस पृष्ठभूमि में चीन में तीन सवरेपरि नेता (राष्ट्रपति) हुए-जियांग जेमिन 15 वर्ष, हू जिंताओ आठ वर्ष और शी चिनफिंग 2012 से लगातार। इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि राजनीति में गठबंधन करके सरकार बनाना गलत है और भारत ने लोकतांत्रिक माध्यम से कभी प्रगति नहीं की। यदि प्रचंड बहुमत के साथ नेतृत्व सशक्त और राजनीतिक इच्छाशक्ति से परिपूर्ण हो, उसके शीर्ष पुरोधा भ्रष्टाचार रूपी दीमक से मुक्त हों और उनकी राष्ट्रहित-जनहित के प्रति नीयत साफ हो तो भी देश की आर्थिक तरक्की संभव है और वह सामरिक रूप से मजबूत हो सकता है। विगत सात वर्षों से भारत उसी आमूलचूल परिवर्तन को अनुभव कर रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था से लगातर दो पूर्ण बहुमत पाकर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राजग सरकार किस गति से काम कर रही है, यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि 1950 से 2014 तक देश में निर्मित राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 91,287 किमी थी तो अकेले मोदी सरकार ने इसमें पिछले सात वर्षों में 45,153 किमी लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग और जोड़ दिए। इस प्रकार के कार्यों की एक लंबी सूची है। सच तो यह है कि अवसरवादी समझौतों की बैसाखी पर खड़ी खिचड़ी सरकारें लोकतंत्र को जिंदा तो रखती हैं, परंतु इससे देश की विकास गति धीमी हो जाती है। देश की एकता, अखंडता, आर्थिक प्रगति और जीवंत लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा वंशवादियों, वामपंथियों, जिहादियों और उस मतांतरण लक्ष्य के साथ चलने वाले स्वयंसेवी संगठनों से है, जो मानवाधिकार, पर्यावरण और आदिवासी आदि कल्याण का मुखौटा पहने रहते हैं और सच-झूठ के विषाक्त घालमेल से देश की विकास यात्र को बाधित करने का प्रयास करते हैं।

क्रिप्टोकरेंसी कारोबार का नियमन हो

क्रिप्टोकरेंसी पर चर्चा तेज हो गई है। इस पर प्रतिबंध लगने की बात हो रही है। सरकार जल्दी ही इस संबंध में कानून ला सकती है। क्रिप्टोकरेंसी दरअसल क्या है, इस सवाल का जवाब अभी तक रिजर्व बैंक और भारत सरकार के पास नहीं है, पर निवेशकों ने इसमें बहुत रकम लगा दी है। भारत में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि सरकारें उन मसलों पर हरकत में बहुत देर में आती हैं, जिन पर उन्हें पहले चेत जाना चाहिए। अब यह बहस शुरू हुई है कि क्रिप्टोकरेंसी के प्रति नीतिगत रुख क्या हो। खबरों के मुताबिक सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया यानी सेबी के नियंत्रण के दायरे में क्रिप्टोकरेंसी का निवेश लाया जा सकता है। पर यह इतना आसान नहीं है। क्रिप्टोकरेंसी है क्या, यह समझना और उसे नियंत्रित किया जाना आसान भले न हो, पर इसके खतरों का सामना देर-सबेर हर बड़ी अर्थव्यवस्था को करना होगा। इस पर बिना वैश्विक समन्वय के कारगर नियंत्रण लगा पाना मुश्किल होगा। क्रिप्टोकरेंसी दुनिया में ऐसी कथित करेंसी है, जिसका भुगतान आतंक से लेकर किसी और चीज के लिए किया जा सकता है। पर इसकी जिम्मेदारी किसकी है, करेंसी का अंतिम भुगतान कौन सुनिश्चित करेगा, यह अभी साफ नहीं है। आतंकी गतिविधियों के लिए क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल संभव है। यानी कुल मिला कर क्रिप्टोकरेंसी से सिर्फ निवेशकों को नहीं, सरकारों को भी खतरा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि क्रिप्टोकरेंसी को करेंसी माना ही नहीं जा सकता, यद्यपि इसकी बिक्री करेंसी के तौर पर ही की जा रही है। किसी प्रपत्र या वस्तु को करेंसी की मान्यता तभी दी जा सकती है, जब यह स्पष्ट हो कि इसका जारीकर्ता कौन है। अमेरिकी डालर करेंसी की जिम्मेदारी अमेरिका की है। भारतीय करेंसी की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक के गवर्नर लेते हैं। यानी करेंसी तभी आधिकारिक करेंसी है, जब कोई उसकी जिम्मेदारी ले रहा हो। क्रिप्टोकरेंसी के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है। निवेश का इतिहास अभूतपूर्व बेवकूफियों से भरा हुआ है और इसे इंसानी लालच का कमाल कहें कि हर बार कोई माध्यम बन ही जाता है इंसानी लालच का। क्रिप्टोकरेंसियां हैं क्या, यह सवाल बहुत महत्त्वपूर्ण है। अक्सर इन्हें एक करेंसी के तौर पर चिह्नित किया जाता है।

● सम्पादकीय

मुश्किल में मुदर्रिस

राजनीति अब जैसे सिर्फ वादों और घोषणाओं का खेल बन चुकी है। जहां सियासी पार्टियों को सत्ता में आने की ललक होती है, वहां चुनाव के वक्त खूब बढ़-चढ़ कर घोषणाएं करती हैं, लोगों को ऐसे-ऐसे सब्जबाग दिखाती हैं कि लगता है, उनके आते ही लोगों के सारे दुख दूर हो जाएंगे। इन घोषणाओं की झड़ी में या तो वे भूल जाती हैं या जानबूझ कर उन पर पर्दा डालने का प्रयास करती हैं कि जो वादे उन्होंने पहले किए थे, वे अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं। या फिर उन्हें इस बात का पूरा यकीन है कि लोगों की याददाश्त कमजोर होती है और वे अब तक उनके पुराने वादे भूल चुके होंगे। कुछ इसी यकीन के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब गए थे। वहां वे स्थायी करने की मांग लेकर आंदोलन कर रहे अस्थायी शिक्षकों के साथ धरने पर बैठ गए और कहा कि अस्थायी शिक्षकों को स्थायी करना तो सरकारों के लिए बहुत मामूली काम है, मगर पंजाब सरकार की नीयत ठीक न होने की वजह से यह काम नहीं हो पा रहा। अगर उनकी सरकार आई, तो वह यह काम पूरा कर देगी। केजरीवाल भूल गए या फिर यह मान बैठे कि लोग भुला चुके होंगे कि यही वादा उन्होंने पहली बार दिल्ली की सत्ता में आने से पहले खुद किया था, जो आज तक पूरा नहीं हो सका है। राजनीति में जुमले उल्टे भी पड़ जाया करते हैं। केजरीवाल के साथ भी यही हुआ। दिल्ली के अस्थायी शिक्षक भी स्थायी करने की मांग के साथ मुख्यमंत्री निवास के बाहर धरने पर बैठ गए। मौका देख पंजाब कांग्रेस के प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू भी उनके साथ धरने पर आ बैठे। स्वाभाविक ही, इससे शिक्षकों का मनोबल बढ़ गया। हालांकि मुख्यमंत्री लापता रहे, शिक्षकों से मिलने नहीं आए और उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ा। केजरीवाल का पंजाब में यह कोई पहला और अकेला वादा नहीं है। इससे पहले वे सभी को मुफ्त बिजली और सभी महिलाओं को हर महीने वजीफा देने की घोषणा कर चुके हैं।

कोई उनसे पूछे कि इसके लिए पैसे आएंगे कहां से, तो शायद उनके पास कोई जवाब न हो। यही हकीकत है राजनीतिक दलों के चुनावी वादों और उनके असल इरादों में। फिर भी हर प्रदेश में चुनावी वादों की बरसात हो रही है और लोग पुलकित हो उसमें भीग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने पहली बार सत्ता में आने से पहले अस्थायी अध्यापकों को स्थायी करने का वादा किया था, मगर सात साल बीत जाने के बाद भी वे इस दिशा में एक कदम आगे नहीं बढ़े हैं। शिक्षकों की स्थिति यह है कि उन्हें दिहाड़ी मजदूरों से भी दयनीय स्थिति में काम करना पड़ता है। सवाल है कि जब शिक्षकों के तय पद खाली हैं, तो उन पर काम कर रहे अस्थायी शिक्षकों को मुस्तकिल करने में अड़चन क्या है। मगर हालत हर जगह यही बनी हुई है। सरकारें धन का रोना रोकर खाली पदों को भरने से बचती रहती हैं। पूरे देश के सरकारी स्कूलों में भारी संख्या में अध्यापकों के स्वीकृत पद खाली पड़े हैं, पर उन्हें भरा नहीं जा रहा। स्थायी होने की लालसा में बहुत सारे लोग अस्थायी रूप में बरसों काम करते रहते हैं, पर सरकारें आखिरकार उन्हें छलती ही हैं। केजरीवाल इसके अपवाद नहीं। मगर दूसरी सरकारों की कमी के रूप में इसका उल्लेख करने से भला बाज क्यों आएं।

वादे और दावे तो बहुत होते हैं पर भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होना नहीं रोक पाईं सरकारें

गौरतलब है कि प्रश्नपत्र लीक होने का ये पहला मामला नहीं है और अंतिम भी नहीं? शासन-प्रशासन के पास इस लीकेज पर लगाम का कोई अखिल भारतीय तरीका भी नहीं। घटनाओं के बाद ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां होना, आरोपियों को जेलों में डालना और कुछ समय बाद जमानत मिल जाना, ये तरीका इस बीमारी का विकल्प नहीं हो सकता? कुछ और मुकम्मल तरीका खोजना होगा। प्रश्नपत्रों को लीक करवाना जालसाजों का पुराना और खानदानी धंधा है। टीईटी परीक्षा लीक प्रकरण में अभी तक जितनी भी गिरफ्तारियां हुईं हैं, वह मोहरे मात्र हैं, बड़ी मछलियां अब भी जाल में नहीं फंसीं। उन तक पहुंचना आसान भी नहीं? दरअसल, इस गोरखधंधे में सफेदपोशों से लेकर और सिस्टम के भेड़िए भी जुड़े होते हैं।

क्या अभ्यर्थियों की किस्मत में यही सब है। भर्ती परीक्षाओं में उनके साथ यूं ही खिलवाड़ होता रहेगा? महीनों मेहनत करेंगे और ऐन वक्त पर जालसाज पानी फेर देंगे? दरअसल यही तो होता आया है बीते कई वर्षों से। व्यवस्थाएं भी बदलीं, सत्ता परिवर्तन भी हुए, लेकिन कल और आज में कुछ खास नहीं बदला? उत्तर प्रदेश में मायावती, मुलायम सिंह, अखिलेश यादव की हुकूमतों से लेकर योगी आदित्यनाथ युग में भी स्थितियां कमोबेश एक जैसे ही रहीं, प्रश्नपत्रों में तब भी लीकेज होता था और अब भी है। कहावत है 'नौ दिन चले ढाई कोस', परिणाम वही 'ढाक के तीन पात'! प्रश्नपत्रों को लीक करवाने में उत्तर प्रदेश में वर्षों से पनपा कुख्यात सिंडिकेट गिरोह एक्टिव मोड में है। बड़ी-छोटी शायद ही कोई ऐसी परीक्षाएं बचती हों, जिनमें ये सेंध न लगाते हों।

अव्वल तौर पर इसमें किसे दोषी ठहराया जाए, परीक्षा नियामक प्राधिकारी को, या फिर सीधे लोक व्यवस्थाओं के रखवालों को? क्या बीतती होगी उन छात्रों पर जो कठिन परिश्रम से परीक्षा देने पहुंचते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि पेपर लीक होने से परीक्षा रद्द हो गई। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा लीक प्रकरण ने व्यवस्था को नए सिरे से सोचने पर मजबूर किया है। यूपी की मौजूदा हुकूमत को पूर्ववर्ती सरकारों के मुकाबले सख्त और पारदर्शी माना जाता है, बावजूद इसके कृत्य वैसे ही हो रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तल्ख लहजे में आरोपियों को चिह्नित कर त्वरित कार्रवाई और दोषियों के विरुद्ध गैंगस्टर-एक्ट लगाने और उनकी संपत्तियों की जब्ती की बात कह दी है।

दरअसल, ऐसा करना जरूरी भी हो गया है, जब तक इनके सिंडिकेट को तितर-बितर नहीं किया जाता, भर्ती परीक्षाओं को लीक प्रूफ करने की परिकल्पना साकार नहीं हो पाएगी। परीक्षा रद्द होने के बाद अभ्यर्थियों से 26 दिसंबर को दोबारा परीक्षा ली जाएगी, जिसके लिए उनसे कोई अतिरिक्त शुल्क व बसों का किराया नहीं लिया जाएगा। पर, क्या ऐसा करने से अभ्यर्थियों ने जो खोया है उसकी भरपाई हो पाएगी? क्या कोई अंदाजा भी लगा सकता है कि कोरोना संकट के बीच उन्होंने किस कड़ी मेहनत से परीक्षा की तैयारियां की होंगी, कोचिंग में धन खर्च के अलावा अपना बहुमुल्य समय भी खपाया, उसका क्या होगा? उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से बड़ा सूबा है। समूचे प्रदेश भर में 2554 केंद्रों पर टीईटी परीक्षाएं होनी थीं। सेंटरों के बाहर दूर-दूर से आए अभ्यर्थियों का जमावड़ा था। भविष्य को संवारने के लिए कितने अरमान लेकर घरों से निकले होंगे, परिजन भी अपने बच्चों की परीक्षा पास की ऊपर वाले से दुआएं मांग रहे थे। लेकिन किसी को क्या पता था कि परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा की जगह उनके साथ मजाक होने वाला है। टीईटी प्राथमिक स्तर की परीक्षा के लिए करीब साढ़े तेरह लाख और टीईटी उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा के लिए 8.93 लाख अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। समझ में नहीं आता इस अपराध को रोकना हुकूमतों के लिए क्यों चुनौती बना हुआ है? देखा जाए तो प्रश्न पत्र बनाने का तरीका बेहद गुप्त होता है, परीक्षा की अंतिम रात तक प्रश्नों पत्रों को संरक्षित रखने की जिम्मेदारी परीक्षा नियामक प्राधिकारियों व सुरक्षाबलों के अधीन होती है। ये जिम्मेदारी चंद विश्वसनीय लोगों के कंधों पर होती है जिसमें कौन-कौन शामिल होते हैं उनकी जानकारियां विभागीय मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक को भी दी जाती हैं। इस दरम्यान कौन सेंध लगा सकता है, उसे दबोचना बहुत आसान होता है। बहरहाल, इस तंत्र में बड़ी मिलीभगत होती है। प्रश्नपत्र लीक प्रकरण की सफलता से कई लोग रातों-रात मालामाल हो जाते हैं। पेपर लीक कांड देश के विभिन्न हिस्सों में समय-समय पर होते रहते हैं। पर उत्तर प्रदेश में ये खेल सबसे ज्यादा खेला जाता है। बदमाशों का ये खेल कितनी परीक्षाओं में सफल हुआ, जिसका हम-आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इनका तंत्र बड़ा जबरदस्त होता है, लेकिन जालसाज टीईटी परीक्षा में गच्चा खा गए। इससे पहले भी एकाध परीक्षाओं में ये लोग नाकाम रहे, जैसे 2017 में सब-इंस्पेक्टर पेपर लीक हुआ, 2018 में यूपीपीसीएल प्रश्नपत्र लीक हुआ, इसी वर्ष पुलिस भर्ती का भी पेपर आउट हुआ। कड़ी लंबी है। 2018 में ही अधीनस्थ सेवा पेपर, स्वास्थ्य विभाग प्रोन्नत पेपर, नलकूप आपरेटर पेपर, 41520 सिपाही भर्ती पेपर लीक हुआ। पिछले साल 69000 शिक्षक भर्ती पेपर लीक हुआ और अब यूपी टीईटी परीक्षा लीक हो गई। ये सिलसिला कब रुकेगा, किसी को नहीं पता? पर, इससे अभिभावकों और परीक्षार्थियों का मनोबल जरूर टूटता जा रहा है।

योजनाएं बेसहारों का सहारा बनें

किसी गरीब परिवार में रोटी कमानेवाला ना रहे, तो परिवार पर अचानक विपदा का पहाड़ टूट पड़ता है। वर्ष 1995 में शुरू हुई राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (एनएफबीएस) का मकसद ऐसे निराश्रित परिवारों को मदद देने का है। दुर्भाग्य से योजना सुस्ती की शिकार रही। इस योजना में आपात सहायता के तौर पर 20 हजार रुपये की मामूली राशि दी जाती है। योजना सिर्फ गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए है और इसमें इतनी औपचारिकताओं को पूरा करना होता है कि किसी का भी धीरज जवाब दे जाये। इसकी यह खस्ताहाली कोई संयोग नहीं है। हाल के वर्षों में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना (एनएसएपी) की अनदेखी की गयी है। मिसाल के लिए, वृद्धावस्था पेंशन के मद में केंद्रीय मद से दी जानेवाली सहायता राशि पिछले 15 सालों से 200 रुपये प्रतिमाह पर ठहरी हुई है। इसे बढ़ाने के लिए बारंबार गुहार लगायी गयी। साल 2018 में 66 नामचीन अर्थशास्त्रियों ने एक खुली चिट्ठी भी लिखी थी, लेकिन केंद्र सरकार टस से मस न हुई। एनएफबीएस का बजट भी ठहरा हुआ है। इस कारण इसका दायरा बढ़ाना या सहायता राशि में इजाफा करना असंभव है। दरअसल एनएफबीएस पर केंद्र सरकार का व्यय 2014-15 के 862 करोड़ रुपये से घटकर 2020-21 में 623 करोड़ रुपये (बजट अनुमान) हो गया और 2020-21 के पुनरीक्षित बजट में यह और भी कम मात्र 481 करोड़ रुपये है।

साफ है कि योजना को धीरे-धीरे खत्म किया जा रहा है। यह और भी दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि एनएफबीएस को मजबूत करने से कोविड-19 के संकट के दौरान लाखों गरीब परिवारों की मदद की जा सकती थी। एनएफबीएस में जान डालना और सुधार करना हिमालय चढ़ने जैसा कठिन नहीं। पहली बात तो यह है कि आपात सहायता राशि में बड़ी बढ़ोतरी हो, जो लंबे समय से प्रतीक्षित है। शुरुआत में यह राशि 10 हजार रुपये थी, जो 2012 में 20 हजार रुपये की गयी। कार्य-बल के सदस्यों में शामिल केपी कन्नन के अनुसार, शुरू में यह सोचा गया था कि एनएफबीएस के अंतर्गत मुहैया कराये जा रहे लाभ की सीमा भारत के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 80 प्रतिशत तक रखी जाये। इसे आधार मानकर अब सहायता राशि बढ़ाकर एक लाख रुपये की जानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि योजना को गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों के लिए सीमित रखने की शर्त हटायी जानी चाहिए। सब जानते हैं कि ज्यादातर राज्यों में बीपीएल की सूची बहुत पुरानी, अविश्वसनीय तथा अपवर्जन की गलतियों से भरी हुई है।

क्या है एमएसपी का स्वरूप, किसान क्या चाह रहे हैं, कानून बनाने से सरकार पर कितना बोझ पड़ेगा?

प्रधानमंत्री के गुरु पर्व के दिन लाइव टीवी पर वादा करने के बाद संसद के शीतकालीन सत्र में तीनों कृषि कानून वापस हो चुके हैं। एक साल से ज्यादा चले किसान आंदोलन के लिए ये एक बड़ी जीत के रूप में देखा गया। लेकिन किसान आंदोलन के नेता अब भी टस से मस होने को तैयार नहीं हैं। इनका कहना है कि उनकी मांग विस्तृत है। सिर्फ कृषि कानून वापस होने भर से उनका आंदोलन वापस नहीं होगा, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी भी चाहते हैं। अभी तक सरकार 23 फसलों पर एमएसपी देती है। लेकिन कुछ भी लिखित में नहीं है। बस किसानों का यही डर है कि ये एमएसपी कभी भी बंद हो सकती है। इसीलिए उनकी मांग ये है कि अब एमएसपी पर कानून बनाया जाए। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान संगठनों की मांग का आधार क्या हैं और क्या ये मांग वाकई पूरी हो सकती हैं।

एमएसपी क्या है : किसानों के हित के लिए एमएसपी की व्यवस्था सालों से चल रही है। केंद्र सरकार फसलों की एक न्यूनतम कीमत तय करती है। इसे ही एमएसपी कहते हैं। मान लीजिए अगर कभी फसलों की क़ीमत बाज़ार के हिसाब से गिर भी जाती है, तब भी केंद्र सरकार इस एमएसपी पर ही किसानों से फसल ख़रीदती है ताकि किसानों को नुक़सान से बचाया जा सके।

कहां से हुई एमएसपी की शुरुआत : 1965 में भारत भीषण अनाज संकट से जूझ रहा था। भारत लाल गेंहू का आयात करने के लिए मजबूर था। जिसे पीएल 480 कहा जाता था। उस दौर में भारत का कोई अनाज बैंक नहीं होता था। भारत के पास पर्याप्त फॉरेन एक्सचेंज भी नहीं था, जिससे हम वैश्विक बाजार से कोई अनाज खरीद पाते। यही से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की शुरुआत हुई। इसके बाद हरित क्रांति आई और आने वाले कुछ सालों में भारत अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। 1960 के दशक में हरित क्रांति में पंजाब की बड़ी भूमिका थी। पंजाब ने गेंहू और चावल उगाना शुरू कर दिया। आज फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास बड़ी मात्रा में अनाज का भंडार है। आज सरकार का अनाज का भंडार 97 मिलियन मिट्रिक टन है। जबकि 1965 में सिर्फ 7 मिलियन मिट्रिक टन अनाज खरीदने के पैसे नहीं थे।

एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी क्यों मांग रहे किसान संगठन : इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार, इस समय केंद्र सरकार ने 23 फसलों पर एमएसपी की घोषणा कर रखी है। इनमें 7 अनाज (धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी और जौ), 5 दालें (चना, अरहर, मूंग, उड़द और मसूर), 7 तिलहन (रेपसीड-सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल) शामिल हैं। इसके अलावा और 4 व्यावसायिक (गन्ना, कपास, खोपरा और कच्चा जूट) शामिल हैं। जबकि एमएसपी तकनीकी रूप से सभी खेती लागतों पर न्यूनतम 50% रिटर्न सुनिश्चित करते हैं, ये अभी तक केवल कागजों पर हैं। भारत के अधिकांश हिस्सों में उगाई जाने वाली अधिकांश फसलों में किसानों को विशेष रूप से फसल के समय प्राप्त होने वाली कीमतें आधिकारिक तौर पर घोषित एमएसपी से काफी कम हैं। चूंकि एमएसपी पर वैधानिक प्रावधान नहीं है, इसलिए किसान अपने अधिकार के तौर पर इसकी मांग नहीं सकते हैं। यही कारण है कि किसान संगठन चाहती हैं कि मोदी सरकार केवल सांकेतिक या वांछित मूल्य के बजाय एमएसपी को अनिवार्य दर्जा देने वाला कानून बनाए।

एमएसपी कैसे लागू किया जा सकता है : पहला तरीका ये है कि निजी व्यापारियों या प्रोसेसर पर दबाव बनाकर उन्हें एमएसपी के तहत भुगतान करने के लिए मजबूर करना। ये पहले से ही गन्ने पर लागू है। चीनी मिलें किसानों को गन्ने के लिए केंद्र के उचित और लाभकारी मूल्य के तहत ही भुगतान करती हैं। कई राज्य सरकारें को तय कीमत से भी ज्यादा देने की कोशिश कर रही हैं। इसके अलावा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जारी गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 जो गन्ना खरीद के 14 दिनों के भीतर कानूनी रूप से गारंटीकृत मूल्य का भुगतान करने के लिए बाध्य करता है। 2020-21 चीनी फसल वर्ष (अक्टूबर-सितंबर) के दौरान, मिलों

ने लगभग 298 मिलियन टन गन्ने की पेराई की, जो देश की कुल उत्पादन 399 मिलियन टन के तीन-चौथाई के करीब था। दूसरा तरीका ये है कि सरकार अपनी एजेंसियों जैसे भारतीय खाद्य निगम, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) और भारतीय कपास निगम के माध्यम से एमएसपी पर खरीद करके इसे लागू कर सकती है। इस तरह की खरीद में पिछले साल भारत के चावल / धान के उत्पादन का लगभग 50% हिस्सा था, जबकि गेहूं के लिए 40% और कपास में 25% से अधिक था। सरकारी एजेंसियों ने भी 2019-20 के दौरान चना (चना), सरसों, मूंगफली, अरहर (कबूतर-मटर) और मूंग (हरा चना) की 0.1 मिलियन टन से अधिक की महत्वपूर्ण मात्रा खरीदी। इसमें से अधिकांश अप्रैल-जून 2020 में कोविड-प्रेरित राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बाद का था, जब किसानों द्वारा सर्दियों-वसंत रबी की फसलों का विपणन किया जा रहा था। हालांकि, इन फसलों की खरीद 2020-21 में गिर गई। सरसों, अरहर, मूंग, मसूर (पीली मसूर) और सोयाबीन के मामले में, खरीद की आवश्यकता वास्तव में महसूस नहीं की गई, क्योंकि खुले बाजार की कीमतें काफी हद तक एमएसपी से ऊपर थीं। तीसरा मार्ग मूल्य की कमी के भुगतान के माध्यम से है। इसके तहत सरकार न तो सीधे खरीद करती है और न ही निजी उद्योग को एमएसपी देने के लिए मजबूर करती है। ये किसानों द्वारा सभी बिक्री को मौजूदा बाजार कीमतों पर करने की अनुमति देता है।

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया बुधवार को रहेंगे नागौर जिले के दौरे पर

कुचामन में कर्नल डिफेंस एकेडमी में होगा भव्य स्वागत

सद्दाम रंगरेज

कुचामनसिटी(नागौर डेली न्यूज) : भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया बुधवार को नागौर दौरे पर आएंगे। कुचामन की प्रतिष्ठित डिफेंस एकेडमी कर्नल डिफेंस एकेडमी के निदेशक कर्नल नन्द किशोर ढाका ने बताया कि पूनिया सुबह नागौर जिले की सीमा में प्रवेश करने पर कुचामन क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेशाध्यक्ष का स्वागत किया जाएगा। इसके बाद कुचामन मेगा हाईवे बाइपास स्थित कर्नल डिफेंस एकेडमी परिसर में प्रात: साढे दस बजे भाजपाइयों द्वारा प्रदेशाध्यक्ष पूनिया का स्वागत-सत्कार किया जाएगा। इसके बाद दोपहर 12 बजे पूनिया चांडी पहुंचेंगे। चांडी में अमर शहीद शिवजीराम रेवाड़ स्कूल परिसर में पूनिया शहीद प्रतिमा का अनावरण करेंगे और स्कूल परिसर की चारदीवारी का लोकार्पण करेंगे। दोपहर 2 बजे वे बड़ी खाटू स्थित सद्गुरू कबीर आश्रम पहुंचेगे। यहां गुरुदेव देवीदास की 7वीं बरसी पर आयोजित संत सम्मलेन समारोह में भी शिरकत करेंगे।

स्कूल छत की मरम्मत के लिए आगे आए भामाशाह

85 हजार का दिया सहयोग

हितेश रारा

मारोठ(नागौर डेली न्यूज) : कस्बे के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छत क्षतिग्रस्त होने पर विद्यालय परिवार द्वारा छत मरम्मत का कार्य करवाया जा रहा है, जिसमें भामाशाहों ने आगे आकर आर्थिक सहयोग दिया है। विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक मंगल चंद घोसलिया ने बताया कि पिछले कुछ माह से विद्यालय में छत रिपेयरिंग का कार्य चल रहा है, जिसमें भामाशाह भागचन्द कुमावत, ओम प्रकाश गौड, रामनारायण कस्वाँ, राजेश गुर्जर वकील, हरिप्रसाद गौड सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य, कमल कुमार, शुभम् कुमार जैन, मूलचंद महर्षि, धन्नाराम चौधरी, सीताराम पूनियां, भंवरसिंह गुर्जर श्रवण कुमार मीणा ने आर्थिक सहयोग दिया है। पूर्व में भी कई भामाशाहों ने सहयोग दिया है, जिससे छत रिपेयरिंग का कार्य चल रहा है। विद्यालय की प्रधानाचार्य सीमा सुण्डा ने इन सब भामाशाह को धन्यवाद दिया और ग्रामवासियों से इस पुनीत कार्य में और सहयोग के लिए आग्रह किया तथा कहा कि विद्यालय स्टॉफ व भामाशाहों के सहयोग से यह कार्य चल रहा है। इस मौके पर व्याख्याता बजरंग लाल, बेबी पंवार, रमेश चन्द सैनी, वरिष्ठ अध्यापक बेगाराम चौधरी, पी.टी.आइ शंकरलाल मीणा, महावीर प्रसाद, सुशीला बेनीवाल, अशोक कुमार, पुस्तकालय अध्यक्ष जुगल किशोर, शिक्षक गंगाधर फुलवारी सहित अनेक लोग उपस्थित रहे।

5 साल से धूल फांक रही है कोर्ट परिसर मे बनी कैंटीन

शौकत खान

डेगाना(नागौर डेली न्यूज) : डेगाना कोर्ट परिसर में वकीलों के चेंबर के साथ बनी कैंटीन पिछले 5 साल से बंद पड़ी है। अधिवक्ता छोटूराम बैडा ओर सुरेन्द्र ढाका ने इसकी जानकारी देकर बताया की कैंटीन संचालन के लिए टेंडर प्रक्रिया नहीं होने के कारण कैंटीन भवन बेकार साबित हो रहा है। ढाका ने बताया की कोर्ट परिसर में वकीलों के चेंबर के साथ ही लाखों की लागत से केंटीन का निर्माण हुआ था, लेकिन टेंडर प्रक्रिया के अभाव मे ये अलीशान भवन पांच सालों से धूल फांक रहा है। 5 वर्ष से ज्यादा समय हो गया, लेकिल अभी भी टेंडर प्रक्रिया शुरू नहीं की गई, जिससे केंटीन भवन बिना साफ-सफाई के और बिना रख रखाव के जर्जर हो रहा है। एडवोकेट सुरेन्द्र ढाका ने कैंटीन शुरू कराने की प्रक्रिया शुरु करने की मांग की है।

उत्कृष्ट कार्य करने पर जिलिया सरपंच सम्मानित

धनसुख सैनी

जिलिया(नागौर डेली न्यूज) : जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला जल एवं स्वच्छता मिशन नागौर के द्वारा जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि जल जीवन मिशन के तहत किए गए कार्यों में गाँवों में ग्रामीणों से शत-प्रतिशत जन सहयोग राशि एकत्रित करवाने वाले सरपंचों को जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। इसी कड़ी में ग्राम पंचायत जिलिया सरपंच गिरधारी राम बावरी को नागौर जिला कलेक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं पुष्प भेंट कर कलक्टरेट सभागार में समस्त जिला अधिकारियों के समक्ष सम्मानित किया गया। नागौर कलेक्टर द्वारा सरपंचो द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की एवं सभी सरपंचों को एवं आमजन को जल जीवन मिशन में अपना सहयोग प्रदान कर इस योजनाओं को सफल बनाने के लिए आह्वाहन किया। इस दौरान जिलिया गांव में सरपंच गिरधारीराम बावरी का हनुमानप्रसाद गुर्जर, नंदकिशोर पुजारी, अशोक कुमार शर्मा, प्रह्लाद शर्मा, पारस जैन ने कार्य की स्वागत किया।

पट्टे बनाए, समस्याएं सुनी

वार्ड संख्या 20 व 21 के लिए आयोजित हुआ शिविर

सद्दाम रंगरेज

कुचामनसिटी (नागौर डेली न्यूज) : नगरपालिका परिसर में मंगलवार को वार्ड संख्या 20 एवं 21 के लिए शिविर आयोजित हुए। शिविर में कृषि भूमि के 36 पट्टे एवं स्टटे ग्रान्ट एक्ट अन्तर्गत 05 पट्टे, 69-ए अन्तर्गत 09 पट्टे एवं भवन निर्माण स्वीकृति के 02 नामान्तरण के 04, पट्टा-पुनर्वेध के 1 प्रकरण निस्तारित किये गये। इसके अतिरिक्त अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के 63 पट्टे एवं 29 जन्म-मृत्यु प्रकरण निस्तारित किये गये। इस प्रकार पालिका में लगभग 13.60 लाख रूपयों का राजस्व प्राप्त हुआ। मंगलवार को शिविर में पानी-बिजली, महिला एवं बाल विकास, चिकित्सा विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के पदाधिकारी एवं प्रतिनिधि भी मौजूद थे, जिनके द्वारा आमजन की समस्याएं सुनी गई एवं निराकरण किया गया। शिविर में पालिका अध्यक्ष आसिफ खान, पालिका अधिशाषी अधिकारी श्रवणराम, कनिष्ठ अभियन्ता रविन्द्र देशवाल, उपाध्यक्ष हेमराज चावला, सम्बन्धित वार्ड पार्षद छीतरमल कुमावत, तुलसीराम कुमावत, बून्दू अली, फारूख कलाल, नरसीराम, भागीरथराम, जवानाराम, अयुब अली, अयुब शेख, सुभाष पनवाडिया, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शेर खान एवं अन्य पार्षदगण व पालिका कार्मिक राजेन्द्र रेवाड़, महेश कुमार, कनवरलाल, महावीरप्रसाद कुमावत आदि उपस्थित रहे।

महिला अत्याचार की रोकथाम व यौन दुराचार के सम्बंध में सजग रहने के लिए हुई 'आवाज दो अभियान' की शुरुआत : आईजी सेंगाथिर

सद्दाम रँगरेज

कुचामन(नागौर डेली न्यूज) : मंगलवार को कुचामन की सामाजिक संस्था कुचामन विकास समिति ओर पुलिस विभाग के तत्वावधान में आवाज दो अभियान के तहत एक सेमिनार का आयोजन हुआ। सेमिनार में अजमेर रेंज आईजी एस सेंगाथिर ओर नागौर जिला पुलिस अधीक्षक अभिजीत सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान बीआर काबरा महिला शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र व एचपी काबरा गर्ल्स कॉलेज की छात्राएं भी उपस्तिथ रही।आईजी एस सेनगाथिर ने कहा कि महिला अत्याचार की रोकथाम, महिला सशक्तीकरण व यौन दुराचार के सम्बंध में सजग रहने के साथ सम्बंधित कानूनों की जानकारी के लिए आवाज दो कार्यक्रम की शुरुवात की गई है।

डेढ़ माह में मिली एक हजार से अधिक शिकायतें

उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत डेढ़ माह में इस तरह के 13 मामलों में पुलिस ने त्वरित कार्यवाही कर आरोपियों को सजा दिलवाई गयी है, जिनमें 2 आरोपियों को फांसी की सजा भी हुई है। आईजी ने बताया कि इस अभियान के शुरू होने के बाद अजमेर रेंज के जिलों में 1000 से ज्यादा ओर सिर्फ नागौर जिले में साढ़े तीन सौ से अधिक शिकायते पुलिस विभाग को मिल चुकी है।

102 आवासीय पट्टे किए जारी, रास्तों के 17 प्रकरणों का किया निस्तारण

लाडनू के मंगलपुरा में आयोजित हुआ प्रशासन गांवों के संग अभियान

अबूबकर बल्खी

लाडनूँ(नागौर डेली न्यूज) : प्रशासन गांवों संग अभियान मंगलवार को ग्राम पंचायत मंगलपुरा में आयोजित किया गया, जहां राजस्व विभाग ने 283 नामांतरण, 278 राजस्व रिकार्ड का शुद्धिकरण, 33 सहमति से खाता विभाजन किए, जिसमें 72 किसान लाभान्वित हुए तथा 17 रास्ते के प्रकरण निस्तारित किए। शिविर में वोटर हेल्प डेस्क ने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने/हटाने/संशोधन से सम्बंधित 15 फॉर्म प्राप्त किए। पंचायत समिति सदस्य निर्मल कुमार प्रजापत के सहयोग से 102 आवासीय पट्टे जारी किए गए। कृषि विभाग ने 100 मृदा स्वास्थ्य नमूने कलेक्ट किए तथा 30 मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण किए। सैनिक कल्याण विभाग ने भूतपूर्व सैनिकों 5 पेंशन प्रकरण तथा 2 अंशदायी स्वास्थ्य योजना के प्रकरण का निस्तारण कैम्प में ही किया गया तथा 1 नया पहचान पत्र जारी किया। जलदाय विभाग ने 18 अवैध कनेक्शन हटाए तथा 65 सेम्पल की गुणवत्ता जांच की, साथ ही 16 पाइप लाइन लीकेज ठीक किए। शिक्षा विभाग ने 17 विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति जारी करवाई तथा 588 बच्चों के जन्मप्रमाण पत्र की अनुज्ञा जारी करवाई। विद्युत विभाग ने कैम्प में ही 2 नए विद्युत कनेक्शन जारी किए व 8 खराब मीटर चेन्ज किए गए। विद्युत सप्लाई में व्यवधान के 4 प्रकरण निस्तारित किए। शिविर में उपखण्ड अधिकारी अनिल कुमार, तहसीलदार कुलदीप भाटी, विकास अधिकारी राजेश्वरी यादव, पंचायत समिति सदस्य निर्मलकुमार आदि का सहयोग सराहनीय रहा।

पाटोदी परिवार ने गौस्वामणी कर खिलाई गायो को लापसी

श्याम सुंदर प्रजापत

कुचामनसिटी(नागौर डेली न्यूज) : मीठड़ी कस्बे की संत गोपाल गौशाला में मंगलवार को गौस्वामणी का आयोजन किया गया। गौशाला अध्यक्ष प्रकाश गंगवाल ने बताया कि गत वर्ष भी तीन माह तक लगातार गौशाला में ग्रामीणों व भामाशाहों के सहयोग से गौस्वामणी क्रम चला था।

इस बार भी आमजन अपने उत्सव, वैवाहिक कार्यक्रम, सालगिरह, जन्मदिन, मृत्यु भोज आदि अवसरों पर गौशाला में गौसेवा बढ़-चढ़कर भागीदारी कर रहे हैं। वहीं गौशाला पदाधिकारियों व गौभक्तो के अथक प्रयासो से आमजन को गौसेवा के प्रति जाग्रत कर आजीवन सदस्य, वार्षिक सदस्य, गौस्वामणी, विभिन्न धार्मिक अवसरो पर कस्बे में वाहन लगाकर घर-घर, दुकान-दुकान से सहयोग राशि एकत्रित कर गौशाला की आमदनी बढ़ायी जा रही है। इसी कड़ी में गौशाला में हर अमावस्या शाम को भजन संध्या का आयोजन रखा जायेगा, जिससे ग्रामीणों को ज्यादा से ज्यादा गौसेवा से जोड़ा जा रहा है। इसी क्रम में आज बस स्टैंड पर जैन मंदिर के पास स्थित पाटोदी परिवार के टीकमचंद पाटोदी, पदमचंद पाटोदी, रिखबचंद पाटोदी ने आदि परिजनो ने गौशाला आकर कर अपने हाथों से गायों को लापसी खिलाकर गौस्वामणी कर पुन्य कमाया। गौशाला पदाधिकारियों ने पाटोदी परिवार का दुपट्टा ओढाकर सम्मान किया। इस दौरान गौशाला अध्यक्ष प्रकाश चंद गंगवाल, गोसेवक बंशीलाल कुमावत, स्वरुप चंद पाटोदी, हरीश पारीक, विजेन्द्र आदि ग्रामीण मौजूद थे।

70वर्षों बाद 30 परिवारों को मिला खातेदारी का हक

- थाटा में खुलेगा मिल्क कलेक्शन सेंटर
- प्रशासन गांव के संग शिविर का आयोजन

शौकत खान

डेगाना(नागौर डेली न्यूज) : मंगलवार को निकटवर्ती ग्राम थाटा में प्रशासन गांवों के संग शिविर का आयोजन हुआ। पिछले 70 वर्षों से सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रहे करीब 30 परिवारों को पहली बार खातेदारी का हक मिला है। एसडीएम मुकेश चौधरी की मौजूदगी में तहसीलदार रामनिवास बाना ने असहमत ऐसे प्रकरणों का निस्तारण करते हुए खातेदारी भूमि का बंटवारा किया।

शिविर में 155 परिवारों को पट्टे भी जारी किए गए। इसके अलावा 130 नामांतरण, 67 शुद्धिकरण, 54 जॉबकार्ड, 20 रोडवेज पास भी वितरित किए गए। गाँव में मिल्क कलेक्शन सेन्टर खोले जाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। इस मौके पर एसडीएम मुकेश चौधरी ने कहा कि आमजन को सरकार की योजनाओं का फायदा दिलाने के लिए प्रशासनिक नुमाइंदों को धरातल पर मेहनत करनी चाहिए। सरपंच कैलाश मेघवाल ने अतिथियों का साफा एवं माला पहनाकर कर स्वागत किया। शिविर में राज्य सरकार के 22 विभागों से जुड़ी योजनाओं से आमजन को लाभान्वित किया गया।

ये रहे मौजूद-

प्रधान जसवंत सिंह, विकास अधिकारी बीरबलसिंह जानू, सरपंच कैलाश मेघवाल, ग्राम विकास अधिकारी महेश दाधीच, रामप्रेम ओलण, जेईएन सतपाल पडगड, अशोक पाराशर, पटवारी सुनीता सारण, दिनेश बेड़ा, भंवर सिंह राठौड़, अशोक दाधीच सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

हताश पैराटीचर्स ने अब सरकार को ललकारा

नियमितीकरण की मांग को लेकर पैराटीचर्स ने निकाली अधिकार महारैली

अबू बकर बल्खी

लाडनूं(नागौर डेली न्यूज) : मदरसा पैराटीचर्स संघ ब्लॉक अध्यक्ष इन्साफ खान के नेतृत्व में संविदा कार्मिकों की नियमितीकरण की मांग को लेकर लाडनूँ मदरसा पैराटीचर ब्लॉक ने नागौर में आयोजित जिला स्तरीय अधिकार महारैली में भाग लिया। इस दौरान पशुमेला प्रदर्शनी से लेकर कलेक्ट्रेट तक नारेबाजी व नियमितीकरण की मांग को लेकर सड़कों पर महारैली निकाली गई। लाडनूँ ब्लॉक कॉर्डिनेटर अख्तर भाटी ने बताया कि शमशेर उर्फ भालू खान के नेतृत्व में पिछले 15 सालों से अल्प मानदेय में मुश्किल से अपने परिवार का गुजारा कर रहे पैराटीचर अपने हक़ की लड़ाई के लिए दो महीने से जयपुर में विभिन्न विधायकों के आवास के सामने धरने पर बैठे ठिठुरते मौसम में संघर्ष कर रहे हैं। संविदाकर्मी इस ठंड के मौसम में राज्य भर मे अनशन कर सरकार से अपनी सेवाओं को नियमित करने की गुहार लगा रहे हैं, मगर सरकार ने अब तक इनकी कोई सुध नहीं ली है। इसके चलते मजबूरन आंदोलन को उग्र करना पड़ेगा। इस मौके पर इन्साफ खान, फरमान खींची, शरीफ तंवर, अख्तर भाटी, सय्यद नदीम, सैय्यद मुश्ताक, वसीम तगाला, खर्शीद, अब्दुल वहीद, मुहम्मद रफीक, आरिफ बल्खी, जहांगीर सौलंकी आदि बड़ी संख्यां में संविदाकर्मी मौजूद रहे।

राजकीय माध्यमिक विद्यालय नंबर 2 अब होगा शहीद अजीम खान विद्यालय

जिला कलेक्टर के प्रयासों से मिली स्वीकृति

अबूबकर बल्खी

लाडनूं (नागौर डेली न्यूज) : देश की सरहदों पर मुल्क की हिफाजत के लिए बलिदान होने वाले वीर शहीदों की याद में सरकारी स्कूलों के नामकरण संबंधी एक और प्रकरण का निस्तारण हो गया है। जिला कलेक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी द्वारा किए जा रहे विशेष प्रयासों के चलते शहीदों की स्मृति में सरकारी संस्थाओं के नामकरण की प्रक्रिया प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रही है। काफी लम्बे समय से लंबित चल रहे अनेकों प्रकरणों का निस्तारण करवाया जाकर शहीदों की स्मृति में सरकारी संस्थाओं का नामकरण किया जाकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देकर आने वाली पीढ़ियों में देश की सुरक्षा करने वालों के प्रति सम्मान पैदा किया गया है। इस संबन्ध में लाडनू का राजकीय माध्यमिक विद्यालय नंबर 2 शहरिया बास अब शहीद अजीम खान पहाडियांन के नाम से पहचाना जाएगा। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के प्रयासों से शिक्षा (ग्रप-6) विभाग के शासन उप सचिव ने नागौर जिले के वीर सपूत शहीद अजीम खान की शहादत की स्मृति में सरकारी स्कूल के नामकरण की स्वीकृति जारी कर दी गई है। इसे लेकर उन्होंने माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक व नागौर के जिला कलक्टर कार्यालय को इस आशय के स्वीकृति पत्र जारी कर दिए हैं।

जिला कलक्टर का जताया आभार

सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल राजेन्द्रसिंह जोधा ने बताया कि शहीद अजीम खान की स्मृति में लाडनू शहर के राजकीय माध्यमिक विद्यालय नं 2 का नामकरण करने की स्वीकृति मो. सलीम खान शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-6) ने जारी की है। सरकारी स्कूल का नामकरण किए जाने की स्वीकृति मिलने पर पूर्व सैनिक कल्याण संघ के ब्लॉक अध्यक्ष केसाराम हुड्डा, विद्यालय विकास समिति के सदस्य मो0 मुश्ताक खान कायमखानी, भामाशाह समाजसेवी लियाकत अली खान, पार्षद हाजी सत्तार खान, पार्षद मुंसफ खान, पार्षद प्रतिनिधि सहाबुद्दीन खान, नगर पालिका चेयरमैन रावत खान सहित समाज के अनेक गणमान्य नागरिकों व शहीदों के परिजनों ने भी जिला कलक्टर का आभार व्यक्त किया है।

1971 के भारत-पाक युद्ध में दी शहादत

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल राजेंद्र सिंह जोधा ने बताया कि लाडनू के वीर सपूत अजीम खान ने वर्ष 1971 में हुए भारत-पाक युद्ध के दौरान सीमा की रक्षा करते हुए मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की शहादत दी थी, जिनकी यादों को आने वाली नस्लों में जिंदा रखने के लिए ये बड़ा कदम उठाया गया।

जिम्नास्टों का किया सम्मान

सद्दाम रंगरेज

कुचामनसिटी(नागौर डेली न्यूज) : 65वीं राज्य स्तर 14 वर्ष छात्र-छात्रा जिम्नास्टिक प्रतियोगिता 2 दिसम्बर से 6 दिसम्बर 2021 तक देचू जोधपुर में आयोजित हुई। जिम्नास्टिक्स खेल प्रतियोगिता का शिक्षा विभाग, निदेशालय बीकानेर से खेल प्रभारी विजय कुमार ओजा ने निरीक्षण किया और विजेता खिलाड़ी छात्र-छात्राओं को पदक पहनाकर सम्मान किया। ओजा ने आयोजकों द्वारा खिलाड़ियों को दी जा रही सुविधाओं पर आभार प्रकट किया ओर प्रशिक्षकों व टीम प्रभारियों से बात कर प्रतियोगिता आयोजन के दौरान व पूर्व प्रशिक्षण तथा राष्ट्रीय प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों व प्रशिक्षकों को आने वाली समस्याओं का निराकरण निदेशक बीकानेर को अवगत करवाकर तुरन्त करवाने का आश्वासन दिया ओर आयोजकों द्वारा दिये जा रही सुविधाओं व मान-सम्मान के लिए शिक्षा विभाग द्वारा आभार प्रकट किया गया।

सेन समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन आज

डेगाना(नागौर डेली न्यूज) :

सेन उत्थान सेवा समिति परबतसर व सेन समाज रुपनगढ़ चमालिसा के संयुक्त तत्वावधान में 8 दिसंबर बुधवार को सेन समाज का विवाह सम्मेलन वीर तेजाजी की पावन धरती सुरसुरा में आयोजित होगा, जिसमें सेन समाज के आराध्य संत अचलानंद महाराज व राजगढ़ धाम के मुख्य उपासक चंपालाल महाराज तथा दयाल पुरी महाराज बाड़मेर के सानिध्य में आयोजित होगा, जिसमें मुख्य अतिथि अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी व विधायक गण, प्रधान, पूर्व विधायक, नगर पालिका चेयरमैन परबतसर ओम प्रकाश सेन, नागौर देहात किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष अमरचंद जाजड़ा सहित कई जनप्रतिनिधि प्रशासनिक अधिकारी, सैन समाज के कई राष्ट्रीय संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। मीडिया प्रभारी भावेश सेन ने बताया कि सैन समाज का विवाह सम्मेलन उत्थान सेवा समिति परबतसर व सेन समाज रुपनगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हो रहा है, जिसमें 16 जोड़ें परिणय सूत्र में बंधगे। विवाह सम्मेलन के प्रवक्ता विक्रम सेन ने बताया कि सम्मेलन में भामाशाह का भी सम्मान किया जाएगा।

मनोज शर्मा बने मंडल अध्यक्ष, कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर

हितेश रारा

मारोठ(नागौर डेली न्यूज) : कस्बे के निकटवर्ती ग्राम श्यामगढ़ निवासी मनोज कुमार शर्मा को भाजपा युवा मोर्चा मारोठ मंडल अध्यक्ष बनाए जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। निर्मल योगी ने बताया कि राजस्थान के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया द्वारा संगठन को मजबूत बनाने के लिए युवा भाजपा मोर्चा मजबूत हो को लेकर भाजपा युवा मोर्चा मारोठ मंडल अध्यक्ष मनोज कुमार शर्मा श्यामगढ़ निवासी को बनाया। मनोज कुमार शर्मा सरल व कर्मठ कार्यकर्ता होने के चलते कार्यकर्ताओं में मजबूत पकड़ रखते हैं। मनोज शर्मा के अध्यक्ष बनने पर कई जनप्रतिनिधि व भाजपा कार्यकर्ताओं ने बधाई संदेश प्रेषित किया।

लोकसभा में राहुल का सरकार पर तंज

पीएम किसानों से माफी मांगते हैं, लेकिन आंदोलन में मरे किसानों की संख्या नहीं जानते

नई दिल्ली।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने किसानों से माफी मांगी और यह माना कि उनसे गलती हुई थी। 30 नवंबर को कृषि मंत्री से पूछा गया कि आंदोलन में कितने किसानों की मौत हुई तो उन्होंने कहा कि उनके पास डेटा नहीं है।

राहुल ने कहा कि पंजाब सरकार ने करीब 400 किसानों को 5 लाख रुपए मुआवजा दिया है और 152 के परिजनों को नौकरी दी है। मेरे पास पूरी लिस्ट है। हमने हरियाणा के भी 70 किसानों की लिस्ट बनाई है, लेकिन आपकी सरकार कहती है कि आपके पास उनके नाम नहीं हैं। वहीं, राहुल गांधी ने प्रदर्शन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को मुआवजा देने के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव भी पेश किया था।

किसानों को मुआवजा नहीं दे रही सरकार

राहुल ने पिछले दिनों कहा कि कोरोना में कितने लोग मरे और कितने किसान मरे, सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। सरकार के पास किसानों, मजदूरों और गरीबों के लिए पैसे नहीं हैं। जब ये शहीद हुए आपने सदन में 2 मिनट का मौन व्रत तक नहीं रखा। अगर वे चाहते हैं तो हमसे लिस्ट लें और 700 परिवारों को मुआवजा दें। हमारे पास 700 में से 500 नाम हैं, जो लिस्ट हमने सरकार को दी। 100 नाम पंजाब से बाहर के हैं। बाकी नाम हमारे पास पब्लिक रिकॉर्ड से हैं। सरकार ने 30 नवंबर को बताया था कि कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान मरे किसानों का आंकड़ा कृषि मंत्रालय के पास नहीं है। लोकसभा में सवाल के लिखित जवाब में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह जानकारी दी थी।

जब तक मैं हूँ, स्कूल की इस जमीन को खुर्द-बुर्द नही होने दूंगा : विधायक डूडी

राजकीय बांगड़ उच्च प्राथमिक विद्यालय में नवनिर्मित बॉस्केट बॉल मैदान का हुआ उद्घाटन

अबरार अली बेरी

डीडवाना (नागौर डेली न्यूज) : राजकीय बांगड़ उच्च प्राथमिक विद्यालय में नव निर्मित बॉस्केट बॉल मैदान का उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक चेतन सिंह डूडी, ओलम्पिक संघ राजस्थान के अध्यक्ष एडवोकेट अजीत सिंह राठौड़, पालिकाध्यक्षा श्रीमती रचना होलानी द्वारा किया गया। इसी के साथ इस बेशकिमती करोड़ों की जमीन से जुड़ी भ्रांतियों और अफवाहों पर भी विराम लग गया है। इस दौरान वरिष्ठ साहित्यकार हाजी सलीम खान पठान, समाज सेवी चेना राम पँवार, हनुमान सिंह, सीबीईओ किशोर राखेचा, पार्षद रघुनाथ दास मोट, गोविंद रुवटिया, प्रधानाध्यापक श्रवण मण्डा मंचस्त रहे।

सरकार खेलों के प्रति सजग है : डूडी

समारोह को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय विधायक डूडी ने कहा कि हमारी सरकार खेलों को लेकर पूर्णत: सजग है। हम ग्रामीण क्षेत्रों में छुपी प्रतिभाओं को ग्रामीण ओलम्पिक खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से उभार कर सामने लाने के सतत प्रयास कर रहे हैं। डूडी ने कहा कि सत्तर सालों से यह जमीन स्कूल के नाम है और जब तक मैं हूँ इस जमीन को कतई खुर्द बुर्द नहीं होने दिया जाएगा। मैं नगर का आश्वस्त करता हूँ कि बहुत जल्द इसी मैदान के पास विधायक कोटे से एक ओर खेल मैदान का निर्माण पूर्ण होगा, साथ इस पूरे परिसर को नगर पालिका जल्द से जल्द साफ करके अन्य खेलों के लिए तैयार कर देगी। उन्होंने खेल एकेडमी के प्रयास तेज करने का भी आश्वासन दिया।

स्कूल की ही रहेगी जमीन : माथुर

पिळती स्कूल के नाम से विख्यात इस स्कूल के खेल मैदान पर लंबे समय से कुछ लोग अपना अधिकार जता रहे थे। हाल ही में न्यायालय में एक वाद भी दायर किया गया, जिस पर अभी तक स्थगन आदेश प्रात नहीं हुवा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पर कभी भी स्थगन आदेश न मिले और यह भूमि इन नो निहालो के खेलने के काम आए। माथुर ने कहा कि कागजात और तथ्य इसे खेल मैदान ही बता रहे हैं ऐसे में विधायक डूडी द्वारा खेल मैदानों के लिए विधायक निधि से खर्च उठाने की घोषणा सोने पे सुहागा सिद्ध होगी ।

डीडवाना बास्केटबॉल का हब बने यही मेरी इच्छा : राठौड़

राजस्थान ओलम्पिक संघ के अध्यक्ष एडवोकेट अजीत सिंह राठौड़ ने कहा कि हम 1994 से लगातार प्रयासरत है कि क्षेत्र में खेलों का सर्वांगीण विकास हो। हम लगातार इसी कोशिश में है कि यहां खेलों के लिए सुविधाएं जुटाई जाए ताकि भविष्य उत्कृष्ट खिलाड़ी तैयार किये जा सके। राठौड़ ने कहा कि आज साथ दशक से देखा जा रहा सपना साकार हुवा है। इसके लिए वरिष्ठ अधिवक्ता राजेन्द्र माथुर, शिक्षक सैयद नईमुद्दीन का हम आभार व्यक्त करते है।

इनका किया गया सम्मान- *समारोह में सिबा कमिश्नर हासम खान, मास्टर नईमुद्दीन, राजेन्द्र माथुर का विधायक डूडी ने माला साफा पहना कर स्वागत किया। समारोह में शकीला परिहार खान, उषा सोनी, लक्ष्मी शर्मा, रेखा जैन, रमाकांत सारस्वत, मोहम्मद नईम खत्री, गोविंद गुर्जर, राजेन्द्र दाधीच, बजरंग सिंह जोधा, बार संघ अध्यक्ष मोहम्मद अली शेरानी, राजकुमार दाधीच, के सी शर्मा, अमजद एच पठान, चेला राम योगी, बृत्म देव शर्मा, देवेश त्रिपाठी, असलम बल्खी, अकरम पठान, सुरेश मारोठिया, अबरार अली बेरी, गुलाब कच्छावा, पीयूष द्विवेदी, विश्नाथ प्रताप सिंह, गुमान सिंह, मुत्तलिब कोटवाल, रमेश वर्मा, विनोद वर्मा, विवेक रंजन सिंह सहित बड़ी संख्या में खिलाड़ी और नगर वासी मौजूद रहे ।*

प्रियंका ने अखिलेश को बताया ज्योतिषी, बोलीं- हमने महिलाओं के लिए बनाया अलग घोषणा पत्र

लखनऊ।

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश पार्टी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ 2 बैठकें हुई हैं। अखिलेश यादव ज्योतिषी हो सकते हैं कि कि उन्हें लगता है कि कांग्रेस को 0 सीटें मिलेंगी। दरअसल, सपा प्रमुख ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलेगी। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि हमने महिलाओं के लिए अलग से एक घोषणा पत्र बनाया है, हम महिलाओं के लिए जो करना चाहते हैं वो उस घोषणा पत्र में होगा।

गांधी का भारत गोडसे के भारत में बदल रहा है, पहले भारत-पाकिस्तान के लोग एक दूसरे के लिए खुश होते थे : महबूबा

नई दिल्ली।

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार को कहा कि महात्मा गांधी का भारत गोडसे का भारत बन रहा है। इस दौरान उन्होंने हाल में हुई कुछ घटनाओं का जिक्र किया, जिनमें भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। मुफ्ती ने याद दिलाया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त दोनों देशों के लोग एक-दूसरे के लिए खुश होते थे।

महबूबा ने कहा कि मुझे वाजपेयी जी के दौर में भारत और पाकिस्तान के बीच एक क्रिकेट मैच याद है। वहां पाकिस्तान के लोग भारत के समर्थन में नारे लगा रहे थे और भारतीय पाकिस्तान के लिए।

तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाने के लिए बेरोजगारों ने दिया ज्ञापन

डेगाना (नागौर डेली न्यूज) : नागौर के प्रभारी मंत्री राजेन्द्र यादव के सोमवार को डेगाना आगमन पर रीट की परीक्षा दे चुके बेरोजगार युवाओं ने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि कोरोना महामारी के कारण रीट भर्ती 2 वर्ष लंबित हो गई, जिसके कारण रीट अभ्यर्थियों बेरोजगारों की संख्या में भी काफी वृद्धि हो गई है तथा साथ ही इन 2 वर्षों में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के भी लगभग 30 से 35 हज़ार पद सेवानिवृत्ति एवं पदोन्नति के कारण रिक्त हो गए हैं तथा शाला दर्पण के अनुसार वर्तमान में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लगभग 55000 पद अतिरिक्त खाली हैं। चूंकि रीट अभ्यर्थियों की संख्या 26 लाख है जो कि आज तक की सभी भर्ती परीक्षाओं में सर्वोच्च संख्या है। इसलिए अब मात्र 31000 पदों पर भर्ती ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। ज्ञापन में बताया की 3 साल के लंबे अंतराल बाद इस भर्ती परीक्षा होने के कारण यह बहुत से अभ्यर्थियों की अंतिम परीक्षा भी हैं। क्योंकि इस परीक्षा के बाद बहुत सारे अभ्यर्थी ओवर एज हो जाएंगे। इसलिए युवाओं ने मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन देकर मांग की कि तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती (रीट) 2021 में पदों की संख्या बढ़ाकर राहत प्रदान करें। ज्ञापन देने वालों में डेगाना विधानसभा के रीट अभ्यर्थी दिनेश कारेल, संदीप पारीक आदि सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी मौजूद थे।

छात्रों व युवाओं की राजनीति समाज के लिए चिंतन का विषय होना चाहिए : पलाड़ा

खो-खो संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व समाजसेवी पलाड़ा का ग्रामीणों ने किया स्वागत

शौकत खान

डेगाना (नागौर डेली न्यूज) : हरसौर कस्बे के एक दिवसीय दौरे पर पहुँचे खो-खो संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं समाजसेवी भंवर सिंह पलाड़ा का ग्रामीणों ने किया अभिनंदन किया।

भाजपा नेता मोहब्बत सिंह गुढा की अगुवाई में ग्रामीणों ने पलाड़ा का साफा एवं माला पहनाकर स्वागत किया। वे जोधपुर से वापस अजमेर जाते समय यहाँ रुके थे। इस अवसर पर समाजसेवी पलाड़ा ने कहा कि मजबूत लोकतंत्र के लिए युवाओं की भागीदारी जरूरी बेहद जरूरी है।

चुनाव के समय हमें युवा शक्ति की याद आती है। छात्रों और युवाओं की राजनीति समाज के लिए चिंतन का विषय होना चाहिए। जब कभी देश में चुनाव की रणभेरी बजी हैं या जब कभी युवा शक्ति ने बड़े आंदोलन को जन्म दिया या किसी घटना विशेष पर अपने आक्रोश से लोगों का ध्यान अपनी और आकर्षित करने में सफल हुए हैं। यह सवाल हमेशा बहस का विषय बना होना चाहिए। इसलिए युवाओं की भागीदारी राजनीति में मजबूत लोकतंत्र के लिए जरूरी है।

सभी समाजों का सामाजिक सामंजस्य होना चाहिये, जिसमें सामाजिक समरसता एवं अन्य गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। इस दौरान प्रधान भाजपा मंडल अध्यक्ष बलबीर सिंह,गोपाल सिंह सथाना,निजी सचिव किशनपुरी सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे।

खुले में सड़क किराने पड़ा सैकड़ों टन कचरा बन रहा है परेशानी का सबब

सद्दाम रंगरेज

आवारा गौवंश के लिए प्लास्टिक कचरा बन रहा है मौत का कारण

कुचामनसिटी(नागौर डेली न्यूज) : एक तरफ से गोवंश को बचाने की मुहिम चल रही है वहीं दूसरी तरफ इन्हें चारा-पानी भी नसीब नहीं हो रहा है। पालने वाले भी दूध देने में सक्षम न होने पर इन्हें आवारा खुला छोड़ देते हैं नतीजन सड़कों पर भटकता गोवंश कूड़ा-कचरा जो भी मिलता है खाने को मजबूर है। इसी के साथ नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही व अनदेखी की सजा बेजुबान जानवरों को मिल रही है। शहर में नगर पालिका द्वारा कचरे का निस्तारण के लिए कोई इंतजाम नहीं है। शहर से बाहर जा रही सड़कों पर कचरे को पाटा जा रहा है। कूड़ा निस्तारण के लिए अब तक जमीनी स्तर पर काम शुरू नहीं किया गया है। नगर पालिका कचरे को सुरक्षित जगह नहीं डालकर कचरे को खुले में सड़कों के किनारे फेंक रही है जिससे नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही अनदेखी की सजा गोवंश व अन्य बेजुबान जानवरों को मिल रही है।

इस बारे में भगतसिंह यूथ ब्रिगेड प्रदेशअध्यक्ष परसाराम बुगालिया व तहसील अध्यक्ष झूमरमल बिजारणिया का कहना है कि नगर को स्वस्थ रखने का दायित्व नगर पालिका प्रशासन का है लेकिन नगरपालिका ने अपने दायित्व से किनारा कर लिया है। इसके पास कचरा प्रबंधन की ना तो कोई व्यवस्था है और ना ही वर्तमान में कोई योजना है।

वर्तमान में नगर पालिका कचरे को सुरक्षित जगह नहीं डाल कर कचरे को खुले में सड़क किनारे डाल रही है जबकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार सड़क किनारे कचरा डालने व जलाने पर प्रतिबंध है फिर भी नगर पालिका कचरे को सड़क किनारे फेंक रही है, जिसमें नगर पालिका की इस लापरवाही की सजा बेजुबान जानवरों को मिल रही है। इसके साथ ही राहगीरों के स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ कर रही है, जिसको लेकर भगत सिंह यूथ ब्रिगेड ने मीडिया के माध्यम से मांग की है कि कचरा सड़क किनारे खुले में ना डाल कर कचरे का निस्तारण की कोई कारागार उचित व्यवस्था करवाई जाए जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव ना पड़े और बेजुबान गोवंश व अन्य जानवरों को कचरा खाने से रोका जा सके।

सारस्वत भाजयुमो जिला आईटी प्रभारी नियुक्त

शौकत खान

डेगाना(नागौर डेली न्यूज) : ग्राम भकरी निवासी कमल सारस्वत को भाजयुमो जिला आईटी प्रभारी किया गया है। भाजयुमो नागौर देहात जिलाध्यक्ष गिरिराज पारीक ने कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए कमल सारस्वत को जिला आईटी प्रभारी नियुक्त किया है। सारस्वत की नियुक्ति भाजपा नेता श्याम माली, सरपंच अख्तर हुसैन, इकाई अध्यक्ष सुशील जैन, सुरजन सिंह, शिंभू सिंह, सदाम देशवाली, जुगल वैष्णव, कमल शर्मा, रामप्रसाद शर्मा सहित पार्टी पदाधिकारियों ने खुशी जाहिर की है।

स्वत्वाधिकारी प्रकाशक, मुद्रक एंव संपादक सद्दाम द्वारा नेशनल प्रिंटर्स, लोहा मंडी, डीडवाना से मुद्रित तथा घाटी कुआँ, छीपा मोहल्ला, कुचामनसिटी, जिला नागौर (राज.) से प्रकाशित। मोबाइल नम्बर 7737211664 Email-nagaurdaily0@gmail.com